शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 36 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 04 – 11 सितम्बर 2023 मूल्य पांच रूपये

क्या मुख्य संसदीय सचिव त्यागपत्र देंगे

- सन्मन न लेने की रिपोर्ट आने पर उच्च न्यायालय ने कहा सम्मन तामिल समझे जायें
- उच्च न्यायालय पहले भी रद्द का चुका है ऐसी नियुक्तियां
- सर्वोच्च न्यायालय जुलाई 2017 में ही कह चुका कि राज्य विधायिका को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है।

शिमला/शैल। सुक्खु सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को चुनौती देती हुई तीन याचिकाएं प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रही हैं। इस मामले की अगली तारीख 18 सितम्बर को है और उसी दिन से प्रदेश विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। इन याचिकाओं में एक याचिका भाजपा विधायकों सर्व़श्री सतपाल सिंह सती, विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा, डॉ. हंसराज, बलबीर वर्मा, राकेश जमवाल, इन्द्र सिंह गांधी, सुरेन्द्र शोरी, त्रिलोक जम्वाल, डॉ. जनक राज, लोकेन्द्र कुमार और दीपराज द्वारा दायर की गयी है। स्पष्ट है कि जब भाजपा के एक दर्जन विधायकों द्वारा यह याचिका दायर की गयी है तो यह पार्टी का सुविचारित फैसला रहा होगा। स्मरणीय है कि एक बार स्व. वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में भी ऐसी नियुक्तियां की गयी थी और उन्हें एक देश बन्धु सूद ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी कि यह नियुक्तियां संविधान का उल्लंघन करती है। उच्च न्यायालय ने यह नियुक्तियां रद्द कर दी थी और इन लोगों को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील से चली गयी थी। हिमाचल की यह अपील असम के मामलों के साथ संलग्न कर दी गयी थी क्योंकि असम में भी ऐसी ही नियुक्तियां हुई थी। इस मामले का फैसला जुलाई 2017 में आ गया और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राज्य विधानसभा इस तरह का कानून बनाने के लिए सक्ष्म ही नहीं है। इस परिदृश्य में यह माना जा रहा है कि वर्तमान नियुक्तियां भी रद्द होगी ही।

कानून की इस पृष्ठभूमि के बाद भी हिमाचल में ऐसी नियुक्तियां करने की अनिवार्यता क्यों आ पड़ी यह प्रश्न अब तक रहस्य बना हुआ है। क्यास लगाये जा रहे हैं कि कहीं उस समय ऑपरेशन कमल का डर तो नहीं हो गया था। क्योंकि जब इन नियुक्तियों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी और अदालत की ओर से सम्मन जारी हो गये तब मामले को लम्बाने की नीयत से इस आश्य के सम्मनों की तामिल को चलने के प्रयास किये गये। ऐसे प्रयास जानबूझकर किये जाने का खुलासा पिछली पेशी में अदालत में उस समय सामने आ गया जब अदालत के सामने सम्मन तामील करवाने गये अधिकारी की यह लिखित रिपोर्ट सामने आ गयी की 15 – 5 – 2023 को संजय अवस्थी के कार्यालय जाकर उन्हें सम्मन दिया और उन्होंने पढ़ा तथा लेने से इन्कार कर दिया। सम्मन सर्वर की इस रिपोर्ट का संज्ञान लेकर अदालत ने यह सुना दिया कि सम्मन सर्व हुये समझ जायें। क्योंकि अदालत में यह आया की कल्पना देवी की याचिका पर सम्मन तामिल हो चुके हैं। तीनों ही यचिकाओं का मुद्दा एक ही है। इसलिये अदालत ने सब याचिकाओं को एक साथ क्लब कर दिया है। इस वस्तु स्थिति में यह सवाल अहम हो जाता है कि भाजपा विधायकों की याचिका पर जारी हुये सम्मनों की तमिल को ही मुख्य संसदीय सचिव टालने और लम्बाने का प्रयास क्यों कर रहे थे। क्या उन्हें ऐसा करने की कोई कानूनी सलाह दी गयी थी या राजनीतिक स्तर पर ऐसा फैसला लिया गया था। भाजपा के एक दर्जन विधायकों की इस याचिका का अर्थ है कि यह पार्टी का बड़े स्तर पर लिया गया फैसला रहा है। ऐसी नियुक्यिां पहले भी रद्द हुई हैं और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्पष्ट है। भाजपा की याचिका में इन नियुक्तियों को रद्द करने के साथ ही इन लोगों को अयोग्य घोषित करने की भी गुहार लगायी गयी है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा ने कानूनी स्थिति को समझ कर ही ऑपरेशन कमल का प्रयास करने की जगह अदालत में यह याचिका दायर करने का फैसला लिया है। क्योंकि यदि अदालत इन नियुक्तियों को रद्द करने के साथ ही इन लोगों को अयोग्य भी घोषित कर देती है तो राजनीतिक समीकरण एकदम से बदल जायेंगे। इनके स्थान पर नये चुनाव करवाने की बाध्यता आ जायेगी। भाजपा ने उस अधिनियम को भी निरस्त करने का आग्रह किया है जिसके तहत इन्हें लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया था। जिस तरह एक सम्मनों की तामिल को टाला जा रहा था उससे अदालत की सहानुभूति मिलने पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योंकि जब ऐसे पदों पर बैठे हुये लोग भी अदालत के प्रति इस तरह का व्यवहार रखेंगे तो उसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाजपा इस याचिका को लोकसभा चुनाव में लाभ लेने का पूरा प्रयास करेगी। अब जब चुनाव तय समय से पहले होने की चर्चाएं चल पड़ी है तब इस मामले को शीघ्र फैसले तक पहुंचाने के प्रयास भी किये ही जाएंगे। ऐसे में भाजपा की गुहार पर भी नजर डालना आवश्यक हो जाता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है की अयोग्यता के तमगे से बचने के लिये यह लोग अपने पदों से त्यागपत्र भी दे सकते हैं।

यह है प्रार्थना

In view of the above, it is respectfully prayed as follows:

A. A writ of Mandamus or any other appropriate Writ or order or direction may be passed directing Respondent no. 1 and Respondent no. 3 to bring the entire record related to Respondent no. 4 to respondent no. 10; AND;

B. A writ Mandamus or any other appropriate Writ or order or direction may be passed to set-aside the Notification dated 11.01.2023 (Annexure P-4) qua the designation of the Deputy Chief Minister upon the Respondent no. 4 as illegal and unconstitutional; AND

C. A writ Mandamus or any other appropriate Writ or order or direction may be passed to the Respondent No. 1 to recover the money spent toward the consequential benefits including the salary given to the Respondent No. 4 to the extent of benefits given above than the designation to the Minister of State.

D. A writ of Mandamus or any other appropriate Writ or order or direction may be passed to restrain the Respondent no. 4 to participate in any Cabinet Meeting.

E. A writ of Mandamus or any other appropriate Writ or order or direction may be passed to quash the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges & Amenities) Act, 2006 along with all the subsequent actions undertaken including the appointments of Respondent no. 5 to Respondent no. 10, as being illegal, irrational and unconstitutional; AND

F. A writ of Mandamus or any other appropriate Writ or order or direction may be passed to quash Section 3(d) The Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971 as being illegal, irrational, and unconstitutional; AND

G. Any other appropriate writ, order or direction as may be deemed fit.

शिक्षक दिवस पर राज्यपाल ने 16 शिक्षकों को किया सम्मानित

शिमला/शैल। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 14 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से और वर्ष 2022 के लिए दो शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने सभी पुरस्कार विजेताओं को पौधे और चित्र भी भेंट किये।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्व. डा. सर्वपल्ली राधकृष्णन के सम्मान में उनकी जन्म जयंती देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। राज्यपाल ने डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धाजंलि अर्पित करते हुए कहा कि वह एक ईमानदार व्यक्तित्व, महान दार्शनिक, प्रख्यात शिक्षाविद् और सक्षम प्रशासक थे। उन्होंने कहा कि उनके विचार भारतीय संस्कृति से गहरे से जुड़े हुए हैं और भारतीय परंपरा से जुड़ी शिक्षा को देश में दोबारा लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगामी 25 वर्षो को अमृत काल कहा है। उन्होंने कहा कि इस अमृत काल में हमें किसी न किसी रूप में देश के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में सक्षम बना सकते हैं।

उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज कई युवा नशे की गिरफ्त में हैं, जो देश के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। नशे के विरूध जन अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कालेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए और उनकी ऊर्जा को समाज निर्माण में लगाने में शिक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का आधार बच्चे को अच्छा इंसान बनाना होना चाहिए। बच्चों के समग्र विकास का उद्देश्य एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करना है। इसलिए शिक्षकों का दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करें।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षण जिम्मेदारी से पूर्ण एक महान पेशा है। शिक्षकों के विचार, आचरण और चरित्र से विद्यार्थी प्रभावित होते हैं, इसलिए उन्हें निष्ठापूर्ण कत्तव्यों का पालन करना चाहिए।

उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए शिक्षक वर्ग को अधिक प्रतिबधता और समर्पण भावना के साथ कार्य करने आहवान किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 34 वर्षो बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। वर्तमान परिदृश्य में सभी को समग्र और सस्ती शिक्षा तथा कौशल विकास प्रदान करने वाली इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसके व्यापक पहलुओं को समझना और इसका सफल कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने एक स्मारिका का विमोचन भी किया।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबध है। उन्होंने कहा कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरक है। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया और इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम किया।

उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग सरकार का सबसे बड़ा विभाग है और इसमें 83 हजार से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। वर्ष 1947 में जहां राज्य की साक्षरता दर मात्र 8 प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर 88 प्रतिशत से अधिक हो गयी है। आज प्रदेश में 140 महाविद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है और राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में भी स्कूल की सुविधा उपलब्ध है, जहां शिक्षक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है तथा नये व्यवसायिक एवं रोजगारोन्मुखी पाठयक्रम आरम्भ किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के रिक्त पद भरे जा रहे हैं और स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट प्रावधान के साथ चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी राजकीय डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है।

इससे पहले, मुख्य संसदीय सचिव, शिक्षा आशीष बुटेल ने राज्यपाल का स्वागत किया और कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समाज में शिक्षकों को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। ऐसे में समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने शिक्षा क्षेत्र में कई मील पत्थर हासिल किये हैं और देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जिसका श्रेय शिक्षकों को भी जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने शिक्षकों को भावी पीढ़ी समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने आहवान किया।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, घनश्याम चंद ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

विधायक विनय कुमार, शिक्षा सचिव डा. अभिषेक जैन, राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, उच्चतर शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा, समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न स्कूलों के शिक्षक, विद्यार्थी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

राष्ट्रीय स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2022

1. श्री वीरेंद्र कुमार, टीजीटी, रा.व.मा.पा., धराग्रा, शिमला।
2. श्री युद्ध वीर, जेबीटी, रा.प्रा.पा., अनोगा, चंबा।

राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2023

1. श्री अमर चंद चौहान, प्रधानाचार्य, रा.व.मा.पा. आनी, जिला कुल्लू।
2. श्री हरि राम शर्मा, प्रधानाचार्य, रा. आदर्श व.मा.पा. नेरवा, जिला शिमला।
3. श्री दीपक कुमार, प्रधानाचार्य, रा. छात्र व.मा.पा. चंबा।
4. श्री अशोक कुमार, रा.छात्र व.मा.पा. मंडी।
5. श्री दलीप सिंह, प्रवक्ता, रा.व.मा.पा. वासानी, सिरमौर।
6. डॉ. रविंदर सिंह राठौड़, प्रवक्ता, रा.व.मा.पा. छोटा शिमला।
7. श्री किशन लाल, डीपीई, रा.व.मा.पा. बजौरा, कुल्लू।
8. श्री हेम राज, टीजीटी, रा.व.मा.पा. हिमरी, शिमला।
9. श्री कमल किशोर, ड्राइंग मास्टर, रा.व.मा.पा. त्यूड़ी, ऊना।
10. श्री किशोरी लाल, सीएचटी, डेरा परोल, हमीरपुर।
11. श्री नरेश शर्मा, एचटी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला, गिरथेरी, हमीरपुर।
12. श्री शिव कुमार, जेबीटी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला, ककराना, ऊना।
13. श्री प्रदीप कुमार, जेबीटी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला, सलोह, सोलन
14. श्री कैलाश सिंह शर्मा, जेबीटी, जीसीपीएस लालपानी, शिमला।

राज्यपाल ने विशेष क्षमता वाले बच्चों के संस्थान ढली का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के निकट ढली में विशेष क्षमता वाले बच्चों के संस्थान बाल का दौरा किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों के कौशल को निखारना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विशेष मार्गदर्शन प्राप्त कर ये, बच्चे समाज के लिए प्रेरणास्रोत साबित हो सकते हैं। उन्होंने संस्थान में छात्रों के लिए कई व्यावसायिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के व्यावसायिक कार्यक्रम उन्हें आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि सभी बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने बच्चों की विशेष देखभाल और उन्हें नियमित शिक्षण के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज विशेष रूप से सक्षम बच्चे कई प्रतिष्ठित क्षेत्रें में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से वे जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं।

उन्होंने संस्थान में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा तथा संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वह सामाजिक संगठनों से भी बात करेंगे ताकि उन्हें संरक्षकता मिल सके।

उन्होंने बच्चों से संवाद किया और मिठाईयां भी बांटी। उन्होंने कहा कि वह इन बच्चों के साथ दीवाली मनाएंगे। उन्होंने परिसर और कक्षाओं का निरीक्षण भी किया तथा नवनिर्मित भवन के बारे में जानकारी ली।

इससे पहले, स्कूल के प्रधानाचार्य धर्मपाल राणा ने राज्यपाल का स्वागत किया और संस्थान में चलाए जा रहे व्यावसायिक पाठयक्रमों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। उन्होंने राज्यपाल को कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के बारे में भी जानकारी दी।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रदीप ठाकुर, अतिरिक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास मोहन दत्त शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी केवल राम चौहान, जिला बाल संरक्षण अधिकारी रमा कंवर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान ढली को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में आज राजभवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल भी बैठक में विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक में शिमला के निकट ढली में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सुंदरनगर स्थित विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान (कन्या) की तर्ज पर ढली स्थित विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान को सरकारी अधिग्रहण में लिए जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि यहां के शिक्षकों और अन्य स्ट फ को भी उचित सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि गत दिवस उन्होंने इस संस्थान का दौरा किया और उन्हें यहां की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

राज्यपाल ने कहा कि यहां अध्ययनरत बच्चों के लिए पर्याप्त स्टाफ की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेष रूप से सक्षम बच्चों का यह एकमात्र संस्थान है और यहां की विशेष आवश्यकताएं हैं। उन्होंने कहा कि अन्य आश्रमों में अपनाई जा रही पक्ति की तुलना इस संस्थान से नहीं की जा सकती। इनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिग्रहण में आने से यह संस्थान और सुदृढ़ होगा।

इस अवसर पर डा.(कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि बाल विकास परिषद द्वारा बच्चों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और विभाग के अधिकारियों द्वारा यहां नियमित रूप से निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर और ढली संस्थान की समस्याओं को दूर करने के दृढ़ प्रयास किए जाएंगे।

बाल कल्याण विभाग की निदेशक रूपाली ठाकुर ने राज्यपाल को संस्थान में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और गतिविधियों से अवगत करवाया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक प्रदीप ठाकुर ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

प्रदेश पर्यटकों के आवागमन के लिए पूर्णत:सुरक्षित:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के नादौन में कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई और निजी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के दृढ़ एवं त्वरित प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में सड़कों को काफी हद तक बहाल कर दिया गया है तथा प्रदेश में आगंतुकों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह राज्य की अब तक की सबसे भीषण त्रासदी थी, लेकिन अब राज्य में हालात सामान्य हो रहे हैं।

नादौन में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए सुरक्षित है और पर्यटक अब चंबा, कांगड़ा, शिमला और अन्य जिलों के भ्रमण पर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने और सभी प्रभावितों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपदा के समय में भी नेता प्रतिपक्ष प्रभावित परिवारों की पीड़ा के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बजाये राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने नेतापक्ष से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क कर हिमाचल प्रदेश के लिए केदारनाथ और भुज त्रासदी की तर्ज पर विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए आग्रह करने का आहवान किया। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और उत्तराखंड और गुजरात में प्रदान की गई सहायता के समान वित्तीय सहायता प्रदान करने की बार-बार अपील की है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के हरसंभव प्रयास कर रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये के ऋण का बोझ डाला तथा केवल राजनीतिक लाभ के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार कर्मचारियों के बकाया और भत्ते देने में विफल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के पश्चात वित्तीय बाधाओं के बावजूद कर्मचारियों के हितों में अभूतपूर्व निर्णय लेकर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है।

आपदा प्रभावित लोगों का पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भारी बारिश व भूस्खलन से प्रभावित लोगों का पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करेगी।

आनी के मुख्य बाजार व पोखरी पंचायत में भूस्खलन ध्वस्त हुए भवनों का जायजा लेने के बाद प्रभावित लोगों से मिल कर उन्होंने उनके दुख दर्द को सुना। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लोगों के भवन पूरी तरह नष्ट हो गए है और जो बेघर हो गए है उनके पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार उन्हें बसाने के लिए उपयुक्त जगह का चयन जल्द किया जाए। प्रतिभा सिंह ने आनी में भूस्खलन से ध्वस्त हुई संपति पर दुख प्रकट करते प्रभावित लोगों से अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से प्रदेश में भारी जानमाल का नुकसान हुआ हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा नुकसान न हो इसके लिए हमें जागृत होना होगा। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ हमें पर्यावरण सरंक्षण की भी चिंता करनी होगी। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि उन्हें अपने भवन वास्तुकार की योजना व पहाड़ की स्थिति के अनुरूप आपदारोधी भवनों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकें।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक प्रदेश को कोई भी विशेष आर्थिक मदद नही मिली हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की एक योजना बनाई है जिसमें प्रदेश में हुई इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाना व राहत व पुनर्वास कार्यो के लिये विशेष आर्थिक मदद की मांग करना हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री प्रदेश की तंगहाल वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रदेश को इस विकट आपदा से निपटने के लिए विशेष आर्थिक मदद जारी करेंगे।

इस दौरान उनके साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेसराम आजाद, यादवेंद्र मिश्रा व पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने जयसिंहपुर और सुलह विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया

शिमला/शैल। मुख्यमत्री ठाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला में जयसिंहपुर और सुलह विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और राहत तथा पुनर्वास कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के नेत्रु गांव में प्रभावित परिवारों से बातचीत

की। नेत्रु गांव में भारी बारिश के कारण कई मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इन परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने देह और कोसरी गांव में पहाड़ी में दरार आने के कारण हुए नुकसान का जायजा भी लिया और जिला प्रशासन को प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुए परिवारों के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय चन्द्रौण में डंगा ढहने से हुए नुकसान का जायजा लिया तथा इसकी मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने इस विद्यालय को अगले शैक्षणिक सत्र से उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की।

उन्होंने सियारा कुडाणा में भारी बारिश और भू-स्खलन के कारण हुए नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी उपायक्तों को ग्राम पंचायतों में वार्ड आधार पर आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित बढ़ी हुई मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज तैयार किया है। इसमें प्रभावितों को प्रदान की जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाया गया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आश्वस्त किया कि उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा हरसंभव मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में पक्के मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर 12,500 रुपये और कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। प्रदेश सरकार ने इस भीषण त्रासदी के दृष्टिगत इस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने न्यूगल खंड में भारी बाढ़ के कारण पपरोला पुल को हुए नुकसान का निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग पर लोक निर्माण विभाग को इस स्थान पर नया पुल बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली, विधायक यादविंद्र गोमा, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उपायुक्त डा. निपुण जिंदल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केन्द्र सरकार ने औद्योगिक विकास योजना के अतिरिक्त कोष को मंजूरी प्रदान की

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निरन्तर प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए औद्योगिक विकास योजना आईडीएस के वित्तीय परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि इस वृद्धि से राज्य के उन उद्यमों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें औद्योगिक विकास योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के बाद सब्सिडी नहीं मिली थी। पूर्व अधिसूचित आईडीएस के अनुसार पहले 131 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय अनुमोदित किया गया था, जो लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए अपर्याप्त था। इसके परिणामस्वरूप पात्र औद्योगिक इकाइयों के लिए सब्सिडी वितरण में देरी हो रही थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के अथक प्रयासों के बाद यह मामला केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया और केंद्र सरकार ने अब हिमाचल और उत्तराखंड के लिए आईडीएस योजना तहत 1164.53 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि संशोधित आईडीएस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में विनिर्माण कार्यो, जैव-प्रौद्योगिकी और जल विद्युत उत्पादन 10 मेगावाट क्षमता की इकाइयों को लाभ होगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में कहीं भी निर्माण और सेवा क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार करने वाली सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को 5.00 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए क्रेडिट तक पहुंच के दृष्टिगत 30 प्रतिशत केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन सीसीआईआईएसी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन-संचालन शुरू होने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए भवन और संयंत्र और मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस बढ़े हुए परिव्यय से हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा और राज्य सरकार, भारत सरकार के साथ लंबित मामलों के पूर्व-पंजीकरण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएगी और योग्य इकाइयों को शीघ्र धन जारी करना सुनिश्चित करेगी।

उद्योग मंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर सृजित करने और क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।

परवाणू और काला अंब 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2023' राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के दो औद्योगिक शहरों परवाणू और काला अंब को प्रतिष्ठित 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023' राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार जिम्मेदार और पर्यावरण के प्रति जागरूक पर्यटन, स्थानीय समुदायों के सक्रिय सहयोग और सरकारी एजेंसियों के समन्वित व निरंतर प्रयासों के कारण संभव हो सका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सतत् विकास हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण-चेतना के बीच सामंजस्य की दृष्टि से प्रदेश हरित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी हितधारकों के सहयोग से 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता राज्य के बजट में स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है, जो हरित ऊर्जा पहल को प्राथमिकता देता है। हिमाचल प्रदेश निरंतर जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ग्रीन कारिडोर स्थापित कर रहा है, जिससे यह अग्रणी कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में सकारात्मक परिणाम आने की आशा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी तीन वर्षों में जीवाश्म ईंधन वाले सरकारी वाहनों का उपयोग धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में सौर एवं पवन ऊर्जा के दोहन के प्रयासों को भी गति प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा, इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करना है बल्कि परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यद्रियों की आय को भी बढ़ावा देना है।

यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नही बिगाड़ सकता।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या सनातन और भारत पर उठा विवाद हिन्दु राष्ट्र का संकेत है

संसद के विशेष सत्र में क्या होने जा रहा है इस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। क्योंकि इस सत्र का एजेंडा अभी तक देश और विपक्ष के सामने नहीं रखा गया है। इस सत्र में प्रश्न काल नहीं होगा। इससे रहस्य और भी गहरा जाता है। क्योंकि विपक्ष को भी यह बताया गया है की समय आने पर कार्य सूची जारी कर दी जाएगी। ऐसे में अटकलें का दौर बढ़ जाता है। इसलिए पिछले कुछ समय में जो कुछ घटा है उस पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। संसद के पिछले सत्र में सरकार ने जन विश्वास विधेयक पारित किया है। इसमें 42 अधिनियमों की 183 धाराओं को जेल की सजा के प्रावधान से बाहर कर दिया गया है इनमें अब जुर्माने का ही प्रावधान रह गया है। इनमें ई.डी, वन, पर्यावरण, बैंकिंग कर्ज, देशद्रोह आदि उन्नीस मंत्रलयों में संशोधन किया गया है। यह संशोधन जीवन यापन और व्यवसाय को सुगम बनाने के लिये किये गये हैं। समरणीय है कि पिछले नौ वर्षो में सरकार जिन कानून के सहारे विरोधियों को घेरती आयी है सरकारें तक गिरायी गयी उनमें अब यह संशोधन इस कार्यकाल के अन्त में क्यों किये गये?

अभी जब विपक्षी दलों ने इक्ठे होकर इंडिया नाम से एक गठबंधन खड़ा कर लिया और इसमें शामिल हर दल और नेता विपक्षी एकता के लिये कोई भी त्याग करने को तैयार हो गया तो इस गठबंधन की गंभीरता स्वत: ही स्पष्ट हो गयी। यह गठबंधन सामने आने के बाद जी-20 सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्षों के नाम राष्ट्रपति की ओर से जो निमंत्रण पत्र भोज के लिए गया उस पर प्रैजीडैण्ट ऑफ इंडिया की जगह प्रैजीडैण्ट ऑफ भारत लिखा गया। अन्य भी सारी संबद्ध सामग्री पर इंडिया के स्थान पर भारत लिखा गया। इस लिखने से इंडिया और भारत पर विवाद छिड़ गया। भारत लिखने की वकालत शुरू हो गयी। यह वकालत शुरू करने वाले यह भूल गये कि जब स्व. मुलायम सिंह यादव इस आश्य का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में लाये थे तब भाजपा ने ही इसका विरोध किया था। यही नहीं 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में आयी इस आश्य की याचिका का यह कह कर केंद्र सरकार विरोध कर चुकी है कि अभी ऐसे हालात नहीं पैदा हुये हैं की इण्डिया का नाम भारत कर दिया जाये। इस आश्य का संविधान संशोधन करने की अभी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में अब ऐसा क्या हुआ है कि यही सरकार इण्डिया की जगह भारत लिखने पर आ गयी है। स्वभाविक है कि इस आश्य का संविधान संशोधन भी कर दिया जायेगा।

जब इण्डिया बनाम भारत का विवाद शुरू हुआ तभी तमिलनाडु के मंत्री उदय निधि का सनातन को लेकर ब्यान आ गया। यह ब्यान किस संद्धर्भ में आया इसकी चर्चा किये बिना ही इसे सनातन धर्म पर हमला करार दे दिया गया। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिये हैं कि वह इस ब्यान का कड़ा विरोध करें। प्रधानमंत्री के इस निर्देश के बाद यह वाक्युद्ध और तेज हो गया है। संभव है कि जी-20 के सम्मेलन के बाद इस विवाद का उग्र रूप भी देखने को मिले। इसी विवाद के बीच एक देश एक चुनाव को लेकर भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गयी है और यह चर्चा चल पड़ी है कि शायद चुनाव ही हो जायें। भारत नाम बदला जाये य सारे चुनाव एक साथ करवाये जायें दोनों ही स्थितियों में संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। एक देश एक चुनाव की संभावनाएं बहुत कम है। क्योंकि जिस तरह से देश में तोड़फोड़ करके सरकारें गिरने की संस्कृति चल निकली है उसके चलते एक चुनाव की व्यवहारिकता बहुत कम रह जाती है। क्योंकि कल यदि कोई सरकार कार्यकाल पूरा किये बिना ही किसी कारण से गिर जाती है तब चुनाव कैसे होगा यह बड़ा सवाल होगा। ऐसे में यही संभावना रह जाती है कि इस विशेष सत्र में हिंदू राष्ट्र की ओर कोई कदम उठाया जाये। क्योंकि आर.एस.एस. को लेकर एक मामला अदालत में चल ही रहा है और उसके परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं। सनातन और भारत पर उठा विवाद इस ओर ज्यादा संकेत कर रहा है।

विज्ञान/ सगोत्री एवं नजदीक के रक्त-संबंधों में विवाह से उत्पन्न होती है अनुवांशिक बीमारियां

गौतम चौधरी

जिस काल में भारत में औरंगजेब का, फ्रांस में लुईस चौदह का शासन था, ठीक उसी समय स्पेन में चार्ल्स द्वितीय शासन कर रहे थे। मात्र तीन वर्ष की आयु में राजा बनने वाला चार्ल्स बचपन से हीं अनेक बीमारियों से पीड़ित और ग्रसित थे। इतिहासकार लिखते हैं - ''चार्ल्स ऐसा राजा था जिसकी शुरुआत ही उसका अंत था, जिसके जन्म से ही लोग उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे।'' ऐसा क्यों हुआ? बड़ा सवाल है।

चार्ल्स, हब्सबर्ग कुल का अंतिम चिराग था, जिसके साथ ही वह कुल समाप्त हो गया। चार्ल्स की तमाम बीमारियां आनुवंशिक रूप से उत्पन्न हुई थी। सात सौ साल तक चले हब्सबर्ग कुल की एक खास बात यह थी कि उस कुनबे में कभी विवाह बाहर नहीं होते थे। अंदर रिश्तों में ही राजा, राजकुमार, राजकुमारियां आदि आपस में विवाह करते थे। चार्ल्स के पिता ने अपनी भतीजी से विवाह किया था। चार्ल्स की मां उसकी रिश्ते में बहन थी। इस कुल में अनेक लोग आनुवंशिक बीमारियों से ग्रसित थे, किंतु चार्ल्स ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई।

इस कुल के मर्दो का एक खास तरह का जबड़ा होता था। चार्ल्स का जबड़ा कुछ ज्यादा बड़ा था। उसका ऊपरी जबड़ा निचले के तुलना में छोटा था। दोनों जबड़े आपस में मिलते नहीं थे। इसके कारण उसे भोजन चबाने में बड़ी दिकत होती थी। दोनों जबड़ा कभी मिलता ही नहीं था। नतीजा वो खाना ढंग से नहीं खा पाता था। वह मानसिक रूप से कमजोर भी था। चार्ल्स किशोरअवस्था तक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता था। बचपन से लेकर मृत्यु तक वो हमेशा बीमार रहा। सब तरह की बीमारियों ने उसे हमेशा अपने चंगुल में दबोचे रखा। यही कारण था कि उसके तरफ से उसकी मां और बहन ने राजकाज संभालती थी।

कुल के लहू की शुद्धता बरकरार रखने के लिए चार्ल्स के दो विवाह हुए। दोनों कुनबे में ही लेकिन बच्चा नहीं हुआ। नामर्दी से लेके तमाम कारण बताये गये किंतु कन्फर्म कुछ नहीं। चार्ल्स के राज्य में स्पेन दो-एक बार दिवालिया भी हुआ। इस काल में स्पेन अमेरिका में खनिज स्वर्ण आदि के दोहन शोषण से पनपा।

सांस की बीमारी, तपेदिक, मानसिक रूप से कमजोर, हमेशा दस्त लगे रहने वाला चार्ल्स जब मरा तब उसकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बड़ी सनसनीखेज थी। जेनेटिक डिसऑर्डर में चार्ल्स का नाम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। गोत्र वाला सिस्टम भारतीय परंपरा का अद्वितीय वैज्ञानिक व्यवस्था है।

यह तो एक उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो यह साबित करने के लिए काफी है कि नजदीक के खून संबंधों में शादी अनुवांशिक बीमारी को आमंत्रित करता है। यही कारण है कि सनातनी हिन्दुओं में सगोत्री शादी पर प्रतिबंध लगाया गया है।

यह विधान केवल सनातनी हिन्दुओं में ही नहीं है। इस मान्यता को आप आदिवासी समाज में भी देख सकते हैं। मेजर ट्राइब हैं, उसमें तो इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाता है। गोंड, संथाल, उरांव, हो, मुंडा के साथ ही अन्य आदिवासी समाज भी इस मान्यता में विश्वास करता है और सगोत्री शादी नहीं करता है।

गोत्र की परंपरा भारत में उत्पन्न लगभग सभी जातियों में देखने को मिलता है। कई जातियां प्रभावशाली जानवरों से अपने आपको जोड़ते हैं जो कई प्रभावशाली वृक्ष से अपनी परंपराओं को जोड़ कर रखे हुए हैं। इसी के आधार पर उनका गोत्र भी चिंहित है। मानव विज्ञान में इसकी व्यापक व्याख्या की गयी है। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि आज जो सनातन हिन्दू धर्म और संस्कृति का स्वरूप है वह आदिवासी समाज की देन है। उसका आधार आदिवासी संस्कृति और धर्म चिंतन है।

बाहरी लोग चाहे जिस किसी कारण से भारत में आए उन्होंने अपना धर्म भी यहां स्थापित किया लेकिन मूल आदिवासी चिंतन को रिप्लेश नहीं कर पाये। गोत्र और शादी-ब्याह की परंपरा आदिवासी मूल परंपरा का ही अवशेष है। इसलिए यह विशुद्ध रूप से भारतीय चिंतन है और लाखों वर्षो का अनुभाव इसके साथ जुड़ा हुआ है।

प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने से ग्राम पंचायतों और युवाओं का होगा आर्थिक सशक्तिकरण

शिमला। प्रदेश सरकार ने राज्य को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में दो-दो ग्राम पंचायतों को पायलट आधार पर हरित पंचायत के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार की है। इन पंचायतों में 500 किलोवॉट से लेकर एक मेगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।

हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार के उपक्रम हिमऊर्जा ने इसके दृष्टिगत ग्राम पंचायतें चिन्हित कर सौर परियोजनाएं स्थापित करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है।

योजना के तहत 500 किलोवॉट क्षमता की सौर परियोजना के निर्माण के लिए 2.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कार्यशील होने के उपरान्त प्रत्येक परियोजना से प्रतिदिन लगभग 2250 यूनिट विद्युत उत्पादन और लगभग 25 लाख रुपये की आय का अनुमान है।

इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इनमें स्थानीय ग्राम पंचायतों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे न केवल स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार बल्कि ग्राम पंचायतों के लिए आय सृजन के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बहु-आयामी प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए युवाओं की भूमिका पर विशेष बल दिया गया है। प्रदेश के युवाओं को अपनी भूमि अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 500 किलोवॉट से दो मेगावॉट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाएगी।

सरकार सार्वजनिक परिवहन को विद्युत परिवहन के रूप में विकसित करने के लिए भी गंभीर प्रयास कर रही है। इससे जीवाश्म इंधन पर निर्भरता भी समाप्त होगी। इस दिशा में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने ई-बस खरीद के लिए 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक का उपदान देने तथा निजी ई-ट्रक की खरीद के लिए भी 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये का उपदान का प्रावधान किया है।

प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने से स्वरोजगार के अनेक साधन उत्पन्न होंगे। संसाधनों के सृजन से युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। इसी दिशा में प्रयास करते हुए सरकार ने विद्युत वाहनों के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत की दर से उपदान प्रदान करने का प्रावधान किया है। इवी-चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार एक वृहद नीति भी तैयार कर रही है।

प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने से न केवल कार्बन उत्सर्जन व प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी बल्कि अनेक क्षेत्रों में नवोन्मेषी पहल से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। हरित ऊर्जा से देश व प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों को बचाने और जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी मदद मिलेगी।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त वक्तव्य

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच घनिष्ठ एवं चिरस्थायी साझेदारी की पुष्टि करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर. बाइडेन, जूनियर का भारत में स्वागत किया। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की जून 2023 की ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा की अभूतपूर्व उपलब्धियों को कार्यान्वित करने की दिशा में हो रही महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की।

दोनों नेताओं ने अपनी सरकारों से विश्वास और परस्पर समझ पर आधारित हमारे बहुआयामी वैश्विक एजेंडे के सभी आयामों में भारत–अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी में बदलाव लाने का काम जारी रखने का आहवान किया। नेताओं ने इस बात पर पुनः जोर दिया कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार, समावेशन, बहुलवाद और सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों के साझा मूल्य, जो हमारे देशों की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और यही मूल्य हमारे संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं।

राष्ट्रपति बिडेन ने यह प्रदर्शित करने के लिए भारत की जी 20 अध्यक्षता की सराहना की कि एक मंच के रूप में जी 20 कैसे महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है। नेताओं ने जी–20 के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी और विश्वास व्यक्त किया कि नई दिल्ली में जी–20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के नतीजे सतत विकास में तेजी लाने, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और बहुपक्षीय विकास बैंकों को मौलिक रूप से नया आकार देने और उनका विस्तार करने सहित हमारी सबसे प्रमुख साझा चुनौतियों से निपटने के लिए समावेशी आर्थिक नीतियों पर वैश्विक सहमति बनाने के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और लचीले हिंद–प्रशांत का समर्थन करने में क्वाड के महत्व की पुनः पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाले क्वाड नेताओं के अगले शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बाइडेन का स्वागत करने के प्रति उत्सुकता व्यक्त की। भारत ने जून 2023 में हिंद–प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) में शामिल होने के अमेरिकी निर्णय के बाद व्यापार कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन से संबंधित आईपीओआई पहल स्तंभ का सह–नेतृत्व करने के अमेरिकी फैसले का स्वागत किया।

वैश्विक शासन व्यवस्था के अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्व पर आधारित होने संबंधी अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार किए जाने और उसमें भारत की स्थायी सदस्यता होने के प्रति अपना समर्थन दोहराया। साथ ही इस संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028–29 में गैर–स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का एक बार फिर से स्वागत किया। नेताओं ने बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत बनाने और उसमें सुधार लाने की आवश्यकता को एक बार फिर रेखांकित किया ताकि यह समकालीन वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सके और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता की स्थायी और गैर–स्थायी श्रेणियों में विस्तार सहित व्यापक संयुक्त राष्ट्र सुधार एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध रहे।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने हमारी रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की तथा हमारे साझा मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने वाले परस्पर विश्वास और भरोसे पर आधारित मुक्त, सुलभ, सुरक्षित और लचीले प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम और मूल्य श्रृंखलाएं बनाने के लिए भारत–अमेरिकी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (आईसीईटी) पहल के माध्यम से जारी प्रयासों की सराहना की। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, सितंबर 2023 में आईसीईटी की मध्यावधि समीक्षा करने के इच्छुक हैं। ताकि 2024 की शुरुआत में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सह–नेतृत्व में अगली वार्षिक आईसीईटी समीक्षा की दिशा में गति बरकरार रह सके।

राष्ट्रपति बाइडेन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में चंद्रयान–3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के साथ–साथ भारत के पहले सौर मिशन, आदित्य–एल1 के सफल प्रक्षेपण पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। अंतरिक्ष सहयोग के सभी क्षेत्रों में नई सीमाओं तक पहुंच कायम करने संबंधी दिशा निर्धारित करने के बाद नेताओं ने मौजूदा भारत–अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह के अंतर्गत वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक कार्य समूह की स्थापना के प्रयासों का स्वागत किया। बाहरी अंतरिक्ष अन्वेषण में हमारी साझेदारी को गहन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित इसरो और नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त प्रयास बढ़ाने हेतु तौर–तरीके, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के बारे में चर्चा शुरू कर दी है और मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग से संबंधित रणनीतिक रूपरेखा को 2023 के अंत तक अंतिम रूप देने की दिशा में प्रयासरत हैं। पृथ्वी और अंतरिक्ष संपत्तियों को क्षुद्रग्रहों और पृथ्वी–समीप वस्तुओं के प्रभाव से बचाने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रह की रक्षा के लिए तालमेल बढ़ाने की भी मंशा रखते हैं। इसमें लघु ग्रह केंद्र के माध्यम से क्षुद्रग्रह का पता लगाने और ट्रैकिंग में भारत की भागीदारी हेतु अमेरिकी समर्थन शामिल है।

दोनों नेताओं ने लचीली वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए अपना समर्थन दोहराते हुए इस संबंध में भारत में अपने अनुसंधान और विकास की उपस्थिति का विस्तार करने के लिए माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी, इंक. की लगभग 300 मिलियन डॉलर का निवेश करने की एक बहु–वर्षीय पहल और भारत में अनुसंधान, विकास और इंजीनियरिंग संचालन का विस्तार करने के लिए एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस की अगले पांच वर्षों में भारत में 400 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा का उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने अमेरिकी कंपनियों, माइक्रोन, एलएएम रिसर्च और एप्लाइड मैटेरियल्स द्वारा जून 2023 में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने सुरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार, लचीली आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक डिजिटल समावेशन के दृष्टिकोण को साझा करते हुए भारत 6जी एलायंस और एलायंस फॉर टेलीकॉम इंडस्ट्री द्वारा संचालित नेक्स्ट जी एलायंस के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने का विक्रेताओं और ऑपरेटरों के बीच सार्वजनिक–निजी सहयोग को गहरा बनाने की दिशा में पहले कदम के रूप में स्वागत किया। उन्होंने ओपन रैन तथा 5जी/6जी प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित दो संयुक्त कार्य बलों की स्थापना को भी स्वीकार किया। फील्ड में तैनाती से पहले एक अमेरिकी ओपन रैन निर्माता द्वारा एक प्रमुख भारतीय दूरसंचार ऑपरेटर में 5जी ओपन रैन पायलट शुरू किया जाएगा। नेताओं ने यूएस रिप एंड रिप्लेस प्रोग्राम में भारतीय कंपनियों की भागीदारी के लिए उत्सुकता प्रकट की (राष्ट्रपति बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में रिप एंड रिप्लेस पायलट के लिए भारत के समर्थन का स्वागत भी किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्वांटम क्षेत्र में भारत के साथ द्विपक्षीय रूप से और अंतरराष्ट्रीय क्वांटम अदान–प्रदान अवसरों को सुविधाजनक बनाने के मंच 'क्वांटम एंटैंगमेंट एक्सचेंज' के माध्यम से मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी (और 'क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसोर्टियम' के सदस्य के रूप में भारत के एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता की भागीदारी का स्वागत किया। यह भी स्वीकार किया गया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे एक अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में शामिल हुआ है।

दोनों नेताओं ने जैव प्रौद्योगिकी और जैव–विनिर्माण नवाचारों में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान सहयोग को सक्षम बनाने के लिए अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन (एनएसएफ) और भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर होने की सराहना की। उन्होंने ने सेमीकंडक्टर अनुसंधान, अगली पीढ़ी की संचार प्रणालियों, साइबर सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों और 'इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम' में अकादमिक और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एनएसएफ और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने का स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने लचीली प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण और रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टमों को जोड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन नीतियों को बढ़ावा देने और नियमों को अपनाने के लिए अपने प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहरायी जो भारतीय और अमेरिकी उद्योग, सरकार और अकादमिक संस्थाओं के बीच अधिक प्रौद्योगिकी साझाकरण, सह–विकास और सह–उत्पादन के अवसरों की सुविधा प्रदान करते हैं। उन्होंने जून 2023 में शुरू किए गए द्विपक्षीय रणनीतिक व्यापार संवाद के तत्वावधान में एक अंतर–एजेंसी निगरानी तंत्र के माध्यम से निरंतर सम्पर्क का भी स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने कम से कम 10 मिलियन डॉलर की संयुक्त प्रारंभिक प्रतिबद्धता के साथ इंडिया–यूएस ग्लोबल चैलेंजिस इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद (आईआईटी काउंसिल) के प्रतिनिधित्व वाले भारतीय विश्वविद्यालयों और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज (एएयू) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरों का स्वागत किया। ग्लोबल चौलेंजिस इंस्टीट्यूट दोनों देशों के अग्रणी अनुसंधान और उच्च–शिक्षा संस्थानों को एक साथ लाएगा, जिनमें एएयू और आईआईटी सदस्यता से परे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए, स्थायी ऊर्जा और कृषि, स्वास्थ्य और महामारी की तैयारी, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और विनिर्माण, उन्नत सामग्री, दूरसंचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम विज्ञान में सहयोग शामिल है।

दोनों नेताओं ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी–टेंडन और आईआईटी कानपुर एडवांस्ड रिसर्च सेंटर और बफ़ेलो में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यूयॉर्क के जॉइन्ट रिसर्च सेंटर्स और आईआईटी दिल्ली, कानपुर, जोधपुर, और बी.एच.यू., के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में साझेदारी सहित बहु–संस्थागत सहयोगात्मक शिक्षा साझेदारियों की बढ़ती संख्या का भी स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने 2030 तक डिजिटल जेंडर गैप को आधा करने की जी–20 की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था में जेंडर डिजिटल डिवाइड को कम करने के प्रयासों के महत्व की पुष्टि की तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था पहल में महिलाओं के प्रति समर्थन व्यक्त किया, जो डिजिटल जेंडर डिवाइड को कम करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र की कंपनियों, प्रतिष्ठानों, सिविल सोसाइटी और बहुपक्षीय संगठनों को एक साथ लाता है।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने अंतरिक्ष और एआई जैसे नए एवं उभरते क्षेत्रों में विस्तारित सहयोग और त्वरित रक्षा औद्योगिक सहयोग के माध्यम से भारत–अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी को गहन और वैविध्यपूर्ण बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी।

दोनों नेताओं ने 29 अगस्त 2023 को कांग्रेस की अधिसूचना की प्रक्रिया पूर्ण होने और भारत में जीई एफ–414 जेट इंजन के निर्माण के लिए जीई एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (एचएएल) के बीच एक वाणिज्यिक समझौते के लिए बातचीत शुरू होने का स्वागत किया तथा इस अभूतपूर्व सह–उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रस्ताव की प्रगति का समर्थन करने के लिए सहयोगात्मक और त्वरित रूप से काम करने की प्रतिबद्धता दोहरायी।

दोनों नेताओं ने अमेरिकी नौसेना और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा अगस्त 2023 में हस्ताक्षरित नवीनतम समझौते के साथ दूसरे मास्टर शिप मरम्मत समझौते के संपन्न होने की सराहना की। दोनों पक्षों ने अग्रिम रूप से तैनात अमेरिकी नौसेना की संपत्तियों और अन्य विमान और जहाजों के रखरखाव और मरम्मत के केंद्र के रूप में भारत के उद्भव को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहरायी। दोनों नेताओं ने विमानों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल से संबंधित भारत की क्षमताओं और सुविधाओं में और अधिक निवेश करने के लिए अमेरिकी उद्योग की प्रतिबद्धताओं का भी स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिकी और भारतीय रक्षा क्षेत्रों के नवोन्वेषी कार्यों का उपयोग करने के लिए एक मजबूत सहयोग एजेंडा स्थापित करने के लिए भारत–अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र (इंडस–एक्स) टीम की सराहना की। इंडस–एक्स ने पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की भागीदारी से आईआईटी कानपुर में आरंभिक एकेडेमिया स्टार्ट–अप पार्टनरशिप का संचालन किया और अगस्त 2023 में आईआईटी हैदराबाद में यू एस एक्सेलरेटर मैसर्स हैकिंग 4 एलाइज़ (एच4एक्स) के नेतृत्व में एक कार्यशाला के माध्यम से भारतीय स्टार्टअप के लिए जॉइंट एक्सेलेरेटर कार्यक्रम की शुरुआत की। दोनों पक्षों ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय के नवाचारों और अमेरिकी रक्षा विभाग की रक्षा नवाचार इकाई द्वारा दो जॉइंट चैलेंजिस शुरू करने की घोषणा का भी स्वागत किया, जो साझा रक्षा प्रौद्योगिकी के समाधान विकसित करने के लिए स्टार्ट–अप को आमंत्रित करेंगी।

राष्ट्रपति बाइडेन ने जनरल 3एटॉमिक्स एमक्यू–9बी (16 स्काई गार्जियन और 15 सी गार्जियन) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और उनके उपकरणों की खरीद के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय से अनुरोध पत्र जारी होने का स्वागत किया। यह विमान खुफिया, निगरानी और सुरक्षा सभी क्षेत्रों में भारत के सशस्त्र बलों की टोही (आईएसआर) क्षमताओं को बढ़ाएगा।

हमारे राष्ट्रों की जलवायु, ऊर्जा परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के एक आवश्यक संसाधन के रूप में परमाणु ऊर्जा के महत्व को दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने सहयोगात्मक मोड में अगली पीढ़ी के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर प्रौद्योगिकियों के विकास सहित परमाणु ऊर्जा में सहयोग में भारत–अमेरिका सहयोग को सुगम बनाने के अवसरों का विस्तार करने के लिए दोनों पक्षों की संबंधित संस्थाओं के बीच गहन परामर्श का स्वागत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह में भारत की सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया और इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ संबद्धता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहरायी।

दोनों नेताओं ने भारत–अमेरिका नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई मंच रूआरई–टीएपी, की अगस्त 2023 में आरंभिक बैठक का स्वागत किया। इसके तहत दोनों देश लैब–टू–लैब सहयोग, पायलटिंग और नवीन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और सक्षम प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए नीति और योजना पर सहयोग, निवेश, इंक्यूबेशन और आउटरीच कार्यक्रमों और नई और उभरती नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा प्रणालियों के उपयोग और उन्हें अपनाने में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास में संलग्न होंगे।

परिवहन क्षेत्र की डीकार्बोनाइजिंग के महत्व को दोहराते हुए दोनों नेताओं ने भारत में इलेक्ट्रिक गतिशीलता के विस्तार की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों कोषों के माध्यम से वित्तपोषित भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए साझा समर्थन शामिल है। इससे पीएम ई–बस सेवा कार्यक्रम में शामिल बसों सहित भारत में निर्मित 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में तेजी आएगी, जिनमें चार्जिंग से संबंधित बुनियादी सुविधाएं मौजूद होंगी। दोनों देश ई–मोबिलिटी के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने में मदद करने की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजी की लागत में कमी लाने और भारत में ग्रीनफील्ड नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी भंडारण और उभरती हरित प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की तैनाती में तेजी लाने के लिए निवेश प्लेटफार्मों के निर्माण को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इस दिशा में, भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष और अमेरिकी विकास वित्त निगम ने नवीकरणीय अवसंरचना निवेश कोष की स्थापना के लिए प्रत्येक को 500 मिलियन डॉलर तक प्रदान करने के आशय पत्रों का आदान–प्रदान किया।

दोनों नेताओं ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लंबित सातवें और अंतिम विवाद के समाधान की सराहना की। ऐसा जून 2023 में डब्ल्यूटीओ में लंबित छह द्विपक्षीय व्यापार विवादों के अभूतपूर्व समाधान के बाद हुआ है।

दोनों नेताओं ने भारत–अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता के तहत महत्वाकांक्षी 'इनोवेशन हैंडशेक' एजेंडा विकसित करने के प्रयासों का स्वागत किया, जिनमें मंदी के समय में दो प्रमुख कार्यक्रम (एक भारत में और एक संयुक्त राज्य अमेरिका में) शामिल होंगे, जिसके अंतर्गत हमारे दोनों पक्ष, दोनों देशों के नवाचार संबंधी इकोसिस्टम के बीच संबंध बनाने के लिए स्टार्ट–अप, निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी फर्म, कॉर्पोरेट निवेश विभाग और सरकारी अधिकारी एक साथ मिलकर सहयोग करेंगे।

दोनों नेताओं ने कैंसर अनुसंधान, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन में हमारे बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग का स्वागत किया और नवंबर 2023 में भारत–अमेरिका कैंसर संवाद के आरंभ होने के प्रति उत्सुकता प्रकट की। यह संवाद कैंसर जीनोमिक्स में ज्ञान बढ़ाने, वंचित शहरी और ग्रामीण समुदायों के लिए कैंसर की देखभाल को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए नए निदान और उपचार विकसित करने पर केंद्रित होगा। दोनों नेताओं ने, दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक, विनियामक और स्वास्थ्य संबंधी सहयोग को मजबूत और सुविधाजनक बनाने के प्रति अपनी साझा संकल्पबद्धता को रेखांकित करते हुए अक्तूबर 2023 में वाशिंगटन डी.सी. में होने वाले आगामी अमेरिका–भारत स्वास्थ्य संवाद पर भी प्रकाश डाला।

द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों के पार्थिव अवशेषों को भारत से वापस ले जाने में सहायता के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग पीओडब्ल्यू/एमआईए अकाउंटिंग एजेंसी और भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (एएनएसआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण का दोनों नेताओं ने स्वागत किया।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने हमारी सरकारों, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच उच्च–स्तरीय संबद्धता बनाए रखने तथा उज्ज्वल एवं समृद्ध भविष्य के लिए हमारे लोगों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने, वैश्विक कल्याण के लिए कार्य करने तथा मुक्त, खुले, समावेशी और लचीले हिंद–प्रशांत में योगदान देने वाली चिरस्थायी भारत–अमेरिका साझेदारी के महत्वाकांक्षी विजन को साकार करने का संकल्प लिया।

राहत शिविरों में रह रहे आपदा प्रभावितों को किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी प्रदेश सरकारः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने योजनाओं व विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण घर क्षतिग्रस्त होने से जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मकान का किराया प्रदेश सरकार अदा करेगी। इसके दृष्टिगत दो व तीन कमरों के सेट किराए पर लेने का प्रावधान किया जाएगा। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। उन्होंने शिमला में विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों व गिरे हुए डंगों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से कृत्रिम मेध (एआई) के पाठयक्रम आरम्भ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भविष्य की चुनौतियों के आधार पर एआई पाठयक्रम आरम्भ करना समय की मांग है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हेलीपोर्टस के निर्माण कार्य की प्रक्रिया की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कटहल की खेती की अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को कटहल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन व समयादेश (अपॉइंटमेंट) के लिए प्रभावी ऑन-लाईन प्रणाली विकसित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने चनौर में ऐतिहासिक शिव मंदिर में शीश नवाया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के चनौर में ऐतिहासिक शिव मंदिर में

शीश नवाया और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए मंदिर के साथ अपने पुराने संबंध को साझा किया और कहा कि मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले भी वह यहां शीश नवाने के लिए अकसर आते रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने ब्यास नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्रशर गतिविधियों पर प्रतिबंध के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे कार्यों को रोकने का निर्णय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत इस मानसून में भारी बारिश से उत्पन्न चुनौतियों के कारण लिया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और राज्य के बुनियादी ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना है। यह प्रतिबंध न केवल कांगड़ा बल्कि कुल्लू, मंडी और हमीरपुर जिलों में भी लागू है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से पर्यावरण संरक्षण और राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र के वन विश्राम गृह डाडासीबा में पौधारोपण भी किया।

इस अवसर पर विधायक संजय रतन व होशियार सिंह, कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया, नरदेव कंवर, डॉ. राजेश शर्मा, उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

बारिश और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को विशेष पैकेज के तहत दी जाएगी राहत राशिः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ऊटपुर

और कक्कड़ सहित अन्य स्थानों पर हुई भारी तबाही के दृष्टिगत जिला प्रशासन को इन्हें आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से बात कर उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित के साथ है। प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से एक-एक पैसा जोड़कर सभी प्रभावितों की मदद करेगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारी बारिश के कारण हुई तबाही के दृष्टिगत राज्य सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें प्रभावितों की सहायता के लिए दस गुणा तक बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित होने के बाद यहां रहने वाले प्रभावित परिवारों को इस विशेष पैकेज के हिसाब से राहत राशि प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पूर्व में पक्के मकान को आंशिक क्षति पर 12,500 रुपये और कच्चे घर को आंशिक क्षति होने पर 10,000 रुपये की राहत राशि दी जाती थी। लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले दुकानों और ढाबों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में सामान के बदले केवल 10 हजार रुपये की आंशिक आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे अब राज्य सरकार ने दस गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा, नए प्रावधानों के अनुसार गाय व भैंस जैसे दुधारू पशुओं की मृत्यु पर प्रति पशु 55,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है और भेड़, बकरी की मृत्यु पर मिलने वाली वित्तीय सहायता को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने सुजानपुर में सचूही, बजाहड़ और जोल पलाही सहित अन्य क्षेत्रों में भी आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और संबंधित विभागों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

प्राकृतिक खेती कृषि आय को दोगुना करने में सक्षम

शिमला/शैल। देश में प्राकृतिक कृषि पद्धति को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के आहवान के साथ डॉ. यशवंत सिंह औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में 'प्राकृतिक खेती: वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं' विषय पर दो सप्ताह का राष्ट्रीय प्रशिक्षण हुआ। इस प्रशिक्षण में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के छह विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों के 21 वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के समापन सत्र के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के अनुसंधान

निदेशक डॉ. संजीव चौहान ने कहा कि हमें कुछ मुद्दों को लक्षित करने की आवश्यकता है जिन्हें इस पद्धति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय देश भर के वैज्ञानिकों को इस पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक कृषि पद्धति पर प्रशिक्षण प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डॉ. चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती से इनपुट लागत को काफी कम करके किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने का रास्ता दिखा सकती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसान प्राकृतिक कृषि फसल मॉडलों के माध्यम से इस कृषि के लाभों को प्रदर्शित करके उदाहरण पेश कर रहे हैं।

इस कार्यक्रम को आईसीएआर राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की संस्थागत विकास योजना द्वारा समर्थित किया गया। परियोजना के मुख्य अन्वेषक डॉ. केके रैना ने प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए आईसीएआर को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि आने वाले हफ्तों में एक अलग समूह के लिए एक और प्रशिक्षण इस विषय पर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण निदेशक डॉ. सुभाष वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण में व्यावहारिक और व्याख्यान-आधारित प्रारूपों के मिश्रण किया और प्राकृतिक खेती के सभी पहलुओं को शामिल किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्राकृतिक खेती से संबंधित विषयों को शामिल करने के अलावा, कृषि में आई.सी.टी. और ड्रोन अनुप्रयोग, कृषि वानिकी का एकीकरण और कृषि-पर्यटन जैसे अन्य विषयों को भी शामिल किया गया। सोलन और शिमला में किसानों के खेतों और मशोबरा में विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र का भी दौरा प्रतिभागियों को करवाया गया।

इस अवसर पर विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ.इंद्र देव, डीन डॉ.मनीष शर्मा और डॉ. सीएल ठाकुर, विभागाध्यक्षों सहित विश्वविद्यालय की प्राकृतिक खेती टीम के सदस्यों ने भाग लिया।

विभागीय परीक्षाओं के लिए आनलाइन आवेदन 8 सितम्बर से

शिमला/शैल। विभाग परीक्षा बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और हिमाचल प्रदेश वन सेवा के अधिकारियों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और हिमाचल में कार्यरत अन्य सभी राजपत्रित एवं पात्र अराजपत्रित अधिकारियों, स्कूल शिक्षा बोर्ड के राजपत्रित अधिकारी, पात्र अराजपत्रित अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अभियन्ताओं व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ प्रबन्धकों, सहायक अभियन्ताओं, राजस्व विभाग के पटवारी व कानूनगो के लिए विभागीय परीक्षाएं 21 से 29 नवम्बर, 2023 तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए पात्र अधिकारियों से 08 सितम्बर से 7 अक्तूबर, 2023 तक मानव संपदा पोर्टल पर आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आवेदन की विंडो स्वत: ही बंद हो जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागाध्यक्षों के अनुमोदन के बाद ही प्रार्थी का आवेदन मान्य होगा और विभागाध्यक्षों के लिए यह विंडो 16 अक्तूबर, 2023 तक खुली रहेगी। इसके बाद विभागाध्यक्ष की विंडो भी बंद हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि विभागीय परीक्षाओं में भाग लेने के इच्छुक पात्र अधिकारियों की सुविधा के लिए सभी पेपर सेंटर आफ एक्सीलेंस, राजकीय डिग्री कालेज संजौली, शिमला में आयोजित करवाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त जो अभ्यार्थी केवल प्रथम पेपर वित्तीय प्रशासन पेपर-1 में भाग ले रहे हैं, उनके लिए राजकीय डिग्री कॉलेज धर्मशाला और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, मण्डी में भी आयोजित करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा की सम्भावित तिथियां हैं और परिस्थितियों के अनुरूप इनमें बदलाव किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और परीक्षा की समय सारिणी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) की वेबसाइट www.hipashimla.nic.in. पर उपलब्ध करवा दी गई है।

ईवीएम और वीवी पैट की प्रथम स्तरीय जांच 16 सितम्बर से

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मनीष गर्ग ने ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने राजनीतिक दलों को अवगत करवाया कि राज्य के ज़िला मण्डी व कुल्लू के अतिरिक्त सभी ज़िलों में ईवीएम और वीवी पैट की एफएलसी 16 सितम्बर, 2023 से तथा ज़िला मण्डी व कुल्लू में यह कार्य 25 सितम्बर, 2023 से आरम्भ किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एफएलसी की शुरूआत से पहले सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) द्वारा सभी राष्ट्रीय व राज्य मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के सभी ज़िला अध्यक्ष व सचिवों को नोटिस जारी किया जाएगा। राजनैतिक दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहचान-पत्र जारी करने के लिए प्रतिनिधियों के पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की एक सूची प्रदान कर आवेदन करना होगा।

उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष व सचिव द्वारा विधिवत प्राधिकृत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मॉक पोल सहित प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की पूरी प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रह सकते हैं। इस प्रक्रिया में ईवीएम और वीवीपैट (एफएलसी) ओके मशीनों में से कुछ मशीनों का मॉक पोल के लिए चयन किया जाएगा। सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रथम स्तरीय जांच एसओपी का अक्षरश: पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिकृत अधिकारी, प्रतिनिधि व कर्मचारी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के माध्यम से पहचान-पत्र प्रस्तुत करने पर ही हॉल में प्रवेश कर पायेंगे। सेलफोन, कैमरा, स्पाई पेन आदि को प्रथम स्तरीय जांच हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी और इन्हें हॉल के बाहर बने संग्रह केंद्र में जमा करवाना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक प्रवेश और निकास को लॉग बुक में दर्ज किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रवेश पर प्रत्येक व्यक्ति, अधिकारी व इंजीनियर की उचित तलाशी की जाएगी। यह कार्य छुट्टियों सहित सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाएगा। प्रथम स्तरीय जांच ओके ईवीएम की सूची राष्ट्रीय व राज्य मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रदान की जाएगी। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एफएलसी के दौरान ओके किए गए मशीन की गुलाबी पेपर सील पर हस्ताक्षर करेंगे। वे मॉक पोल के लिए ऐच्छिक रूप से ओके मशीन चुन सकते हैं। वेयरहाउस व स्ट्रांग रूम खोलने और सील करने के समय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनर्रीक्षण कार्यक्रम-2024 के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई व अवगत करवाया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 25 के प्रावधानानुसार 02 सितम्बर, 2023 को मतदान केन्द्रों की सूचियां प्रारूप में प्रकाशित कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रारूप में प्रकाशित सूचियों समस्त जिला निर्वाचन कार्यालयों समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप मण्डलाधिकारी(ना), समस्त तहसीलों व उप-तहसीलों के कार्यालयों में जनसाधारण के निरीक्षण के लिए 08 सितम्बर, 2023 तक उपलब्ध रहेंगी। इस दौरान यह सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हि.प्र. की वेबसाइट *https://ceohimachal.gov.in* पर भी देखी जा सकती हैं। बैठक में निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ऑनलाइन पोर्टल पर्यावरण नवाचार पहल को बढ़ावा देगा

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पर्यावरण के संरक्षण और इस दिशा में सहयोगात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित एनजीओ पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रस्तुत किया गया है। पर्यावरण संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार इस मंच के माध्यम से संगठनों से लेकर राज्य सरकार के बीच एकता और तालमेल को बढ़ावा देगी।

उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर पंजीकरण करके, गैर सरकारी संगठन बड़े पैमाने पर समाज पर अपना प्रभाव बढ़ाने के अवसरों से अवगत होंगे। इस पोर्टल के माध्यम से एनजीओ/सीबीओ संसाधनों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार को बढ़ावा देने, विचारों के प्रवाह को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है जो सामूहिक प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है।

इस पोर्टल के माध्यम से, गैर सरकारी संगठन पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार साझा करने के लिए साथी संगठनों, सरकारी निकायों और हितधारकों के साथ समन्वय कर सकते हैं। इस तरह का समन्वय रणनीतिक साझेदारी, संयुक्त पहल और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण पर दृश्यता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

इसमें कार्यशालाएं, कौशल विकास कार्यक्रम और प्रासंगिक शैक्षिक सामग्री तक पहुंच भी शामिल है। पर्यावरणीय चुनौतियों से अधिक कुशलता से निपटने के लिए संगठनों की क्षमता विकास को मजबूत करना भी इसका उद्देश्य है। इस पोर्टल पर पंजीकृत एनजीओ को विभागीय वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफार्म और जागरुकता अभियानों सहित विभाग के संचार चैनलों के माध्यम से बढ़ती दृश्यता और एनजीओ के बारे में सार्वजनिक जागरुकता बढ़ाने से लाभ होगा। गैर सरकारी संगठन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कर, प्रदेश के पर्यावरण की सुरक्षा के आंदोलन में अभिन्न भागीदार बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठनों की विशेषज्ञता और योगदान प्रदेश के स्थायी भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि संगठन वेबसाइट लिंक https://agisac.gov.in/envgis/NGo_Home.aspx पर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आने वाली कठिनाई और अन्य जानकारी के लिए बलदेव राज ठाकुर कम्प्यूटर प्रोग्रामर के मोबाइल नंबर 7018355400 और 9418455400 पर संपर्क कर सकते हैं।

पर्यटकों के स्वागत के लिए हिमाचल तैयार

शिमला/शैल। देश का प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्य हिमाचल प्रदेश एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक अमित कश्यप ने बताया कि पर्यटक कसौली, शिमला, चायल, नारकंडा और किन्नौर जैसे खूबसूरत पर्यटन गंतव्यों की यात्रा और भ्रमण कर सकते हैं। इन पर्यटन गंतव्यों के लिए सड़क मार्ग खुले हैं और कोई भी इन गंतव्यों की सुरक्षित यात्रा कर सकता है।

उन्होंने बताया कि कांगड़ा घाटी, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, पालमपुर, डलहौजी, खज्जियार और चम्बा के भ्रमण के लिए भी सड़क मार्ग खुले हैं। पर्यटक वर्तमान सीजन में राज्य के अधिकांश होटलों में विशेष छूट की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 7 प्रतिशत है। इसके अलावा, पर्यटन क्षेत्र राज्य में कुल रोजगार में लगभग 14.42 प्रतिशत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का योगदान देता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग से यात्रा के लिए राज्य के कुछ हिस्सों में व्यवधान उत्पन्न हुआ, हालांकि सड़क मार्गों को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर किये गए प्रयासों से पर्यटक अब चम्बा, कांगड़ा, शिमला और अन्य जिलों की यात्र कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से शिमला से धर्मशाला के लिए हवाई सेवा कनेक्टिविटी प्रदान की गई है और अब दिल्ली से शिमला और शिमला से धर्मशाला (गग्गल हवाई अड्डा) के लिए अलायन्स एयर की दैनिक उड़ान भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि शिमला-धर्मशाला-शिमला की सभी सीटों के किराये पर सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। इस रूट पर कुल किराया प्रति सीट 3000 रुपये (टैक्स अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की सुविधा के लिए उड़ान योजना के अंतर्गत पवन हंस द्वारा संचालित हेलीकाप्टर सेवा की उड़ानें चंडीगढ़ से शिमला और शिमला से रामपुर, मंडी, कुल्लू तथा धर्मशाला के लिए उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की सहायता के लिए ओडिशा सरकार का आभार व्यक्त किया

शिमला/शैल। ओडिशा सरकार ने आपदा राहत कोष-2023 के लिए हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उदारतापूर्ण सहायता के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने में प्रदेश सरकार को मदद मिलेगी।

उन्होंने आम लोगों से आपदा राहत कोष में उदारतापूर्वक योगदान का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रा तिक आपदा से प्रभावितों को सहयोग और सहायता सुनिश्चित करने के लिए देश भर के लोगों के सामूहिक प्रयास और योगदान सराहनीय हैं।

10 में 9 विधानसभा सीटें भाजपा की झोली में डालने का खामियाजा भुगत रही है मंडी की जनता:बिंदल

शिमला/शैल। सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी से 80 कॉलेज निकाल कर दूसरे विश्वविद्यालय में डालने

के प्रदेश सरकार के फैसले के बारे में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, डॉ राजीव बिंदल, ने कहा कि यह फैसला अत्यन्त दुखदाई है और हिमाचल प्रदेश तथा विशेषतौर से मंडी क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय और धोखा है।

डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि मंडी क्षेत्र में पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय खोला गया था। इस विश्वविद्यालय को खोलने से हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिला। विद्यार्थियों को किसी और विश्वविद्यालय में डिग्री संबंधि या किसी अन्य कार्य हेतु होने वाले व्यय में कटौती हुई और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ौतरी हुई। मंडी का क्षेत्र दूरदराज तक फैला हुआ है, न केवल मंडी अपितु कुल्लू व लाहौल स्पीति जिला इस सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे में 80 कॉलेजिज को सरदार पटेल विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

डॉ बिंदल ने कहा कि वास्तव में कांग्रेस की वर्तमान सरकार इस विश्वविद्यालय को बंद करना चाहती है और बंद करने से पहले इस विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजिज को निकाल कर इसे खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी ने यह भी आरोप लगाया, क्योंकि मंडी में 10 में से 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत के आये हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी मंडी की जनता को सजा देने में लगी है।

भाजपा ने कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा व मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह से भी यह पूछा है कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय उनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और इस विश्वविद्यालय से 80 कॉलेजिज को निकाल दिया गया है और इस विश्वविद्यालय को बंद करने का षडयंत्र उन्ही की कांग्रेस सरकार कर रही है, इस पर प्रतिभा सिंह शांत क्यों हैं?

भाजपा अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि इस विश्वविद्यालय को बंद करने में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा पूरी तरह शामिल है।

9 महिने पहले सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने केवल और केवल संस्थानों को बंद करने का काम किया है। 1500 संस्थानों को ये सरकार पहले ही बंद कर चुकी है। अस्पतालों, पी. एच.सीज., सी.एच.सजी., पटवार सर्कल और स्कूलों को बंद करना दुखदाई है। कांग्रेस सरकार इस क्षेत्र की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रही है और उसी कड़ी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय को बंद करने का षडयंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी।

भाजपा विधायक विनोद कुमार पर एफआईआर निंदनीय :रणधीर शर्मा

शिमला/शैल। वर्तमान कांग्रेस सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही हैं , यह आरोप भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने लगाया हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने

पिछले दिनों नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार पर एफआईआर कर निंदनीय कार्य किया हैं। उन्होंने कहा कि एक विधायक द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाना , उन विषयों पर अधिकारीयों से मिलना और उनकी चर्चा करना हर विधायक का कर्तव्य हैं। उन्होंने कहा कि उन समस्याओं का हल न होने पर ऊँची आवाज़ में भी बात करनी पड़ सकती हैं। पर उस पर यह भेदभाव पूर्ण कार्य करना सरकार को शोभा नही देता हैं।

शर्मा ने कहा कि यह विषय मात्र नाचन का नही हैं, कुछ लोगों को राहत मिलना कुछ को राहत न मिलना भेदभाव पूर्ण कृत्य हैं। प्रशासन द्वारा विधायक की बात को न सुनना सरकार की तानाशाही प्रवृति को दर्शाता हैं। विधायक दल इसकी कड़ी निंदा करता हैं और इस एफआईआर को जल्द वापिस लेने की मांग करता हैं।

उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को विधानसभा सत्र में भाजपा इस विषय को जोर शोर से उठायगी। शर्मा ने सरकार को चेताया की कांग्रेस सरकार के भेदभाव पूर्ण कार्य व बंदर बांट को नही रोका गया तो भाजपा सदन के साथ साथ सदन के बाहर भी इस विषय को उठाएंगे और इसको जनआंदोलन बनाएंगे। ताकि बहरी सरकार को लोगों की समस्याएं सुनाई दे जाए या दिखाई दे जाए और लोगों को न्याय मिल सके।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

कांग्रेस की प्रक्रियाओं के बावजूद प्रदेश हित में सुक्खु शामिल हुए भोज में

प्रधानमंत्री से मिलकर मांगी और राहत

शिमला/शैल। इस समय सरकार और इंडिया गठबंधन में कैसे रिश्ते चल रहे हैं यह पूरे देश को पता है इसमें भी गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस के साथ रिश्तों की परकाष्ठा यहां तक पहुंच गयी है कि राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को जी-20 शिखर सम्मेलन में आये विदेशी मेहमानों के स्वागत में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये राजकीय भोज में आमंत्रित नहीं किया गया। जबकि सारे मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख लोग इसमें आमंत्रित थे। खड़गे को न बुलाये जाने पर पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने भी इसकी निन्दा की है। कांग्रेस के तीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भुपेश बघेल और सिद्धारमैय्या ने जो भोज के लिए आमंत्रित थे इससे किनारा रखा। भले ही इन

मुख्यमन्त्रियों ने अपने-अपने कारणों से भोज से दूरी रखी। लेकिन कांग्रेस के ही चौथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह राहुल और चिदम्बरम की प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस भोज में शामिल हुये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर हिमाचल में बरपी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और भूज तथा केदारनाथ की तर्ज पर हिमाचल को राहत देने का भी आग्रह किया। इस आपदा में हिमाचल में बारह हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। 400 से अधिक लोगों की जान गयी है। हजारों लोगों की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार को अपने ही संसाधनों से इस नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। फिर प्रदेश सरकार की कर्ज लेने की सीमा पर भी कटौती कर दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठकर प्रदेश हित में इस भोज में शामिल होने का फैसला लिया और प्रधानमंत्री से मिलकर सहायता की मांग भी की। अब यह देखना रोचक होगा कि इससे प्रदेश को कोई सहायता मिल पाती है या नहीं। इस समय हिमाचल इस प्राकृतिक आपदा के साथ ही राजनीतिक आपदा से भी गुजर रहा है। हिमाचल में बनाये गये मुख्य संसदीय सचिवों का मामला उच्च न्यायालय में गंभीर मोड पर पहुंच चुका है। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले इन नियुक्तियों के खिलाफ है। प्रदेश उच्च न्यायालय तो पूर्व में भी ऐसी नियुक्तियों को रद्द कर चुका है। ऐसे में इस फैसले का कांग्रेस ही नहीं पूरे प्रदेश की राजनीति पर असर पड़ेगा। ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि भाजपा इस मामले में आगे कितनी सक्रियता से बढ़ती है क्योंकि कांग्रेस के कुछ हल्कों में यह भी चर्चा है कि सब कुछ मैनेज हो जायेगा।

प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिये जमीन पर क्या किया गया-जय राम

बिजली की दरें बढ़ने से उद्योगों पर पड़ेगा नकारात्मक असर

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये कितने युवाओं को मिली है 40% सब्सिडी

कितनी पंचायतें हो पायी है ग्रीन कितने सौर ऊर्जा संयन्त्र लग पाये है?

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक ब्यान में सरकार से पूछा है कि बजट में घोषित हरित प्रदेश बनाने से जुड़ी योजनाओं पर कितना काम हुआ है और कितने लोगों को लाभ मिला है। स्मरणीय है कि सुक्खु को सरकार ने सत्ता संभालते ही प्रदेश को हरित राज्य बनाने की घोषणा की थी। प्रदेश में डेढ़ हजार इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा एचआरटीसी शामिल करने और निजी बसों के संचालकों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेने पर सब्सिडी देने की घोषणा की थी। 2025 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात की थी। कांगड़ा और हमीरपुर में पेट्रोल डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की बात की थी। पहले चरण में 150 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने और 50 अलग-अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की बात की थी। 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। 2024 के अन्त तक 500 मैगावाट के सौर ऊर्जा संयन्त्र और हर जिले की दो पंचायतों को ग्रीन पंचायत विकसित करने की घोषणा की थी। इसके लिये 250 किलोवाट से लेकर दो मैगावाट के सोलर प्लांट लगाने के लिये 40% सब्सिडी और उत्पादित बिजली को खरीदने की बात की थी। यह सारी घोषणाएं और वायदे बजट सत्र में किये गये थे।

सरकार बने नौ माह हो गये हैं और बजट सत्र को भी हुये छः माह का समय हो गया है। स्वभाविक है कि इस अवधि में इन घोषणाओं पर कुछ तो अमल हुआ होगा। अब विधानसभा सत्र आ रहा है। इस सत्र में विपक्ष सरकार को उसी की घोषणाओं पर घेरेगा। क्योंकि जमीन पर इस दिशा में संतोषजनक कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि यह सरकार भी विकास के नाम पर हजारों करोड़ का कर्ज ले चुकी है। पूर्व सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डूबने के जो आरोप लगाये जाते थे आज यह सरकार स्वयं भी उसी कर्ज के सूत्र पर आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि पिछली सरकार को लेकर जो वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का वायदा किया गया था अब वह चर्चा से भी बाहर हो गया है। बल्कि सत्ता में आने पर हर उपभोक्ता वस्तु के दामों में वृद्धि ही हुई है। सेवाओं और वस्तुओं के दाम बढ़ाकर ही संसाधन बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अभी बिजली के शुल्क डेढ़ गुना बढ़ा दिये गये हैं। इसका असर प्रदेश के उद्योगों पर पड़ेगा। इस आपदा के समय में सीमेन्ट के दाम भी बढ़ जायेंगे जिसका सीधा प्रभाव राहत कार्यों पर पड़ेगा।

बिजली की दरें बढ़ाने से नयी दरों के तहत एच.टी. के अधीन आने वाले उद्योगों का शुल्क 11% से बढ़कर 19% ई.एच.टी. का 13% से 19% और छोटे तथा मध्यम उद्योगों को 11% से 17% सीमेन्ट सयंत्रों पर 17% से 25% तक कर दिया है। यही नहीं डीजल जेनरेटर द्वारा बिजली उत्पादन पर 45 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क भी लगाया गया है। जयराम के मुताबिक उनकी सरकार ने उद्योगों को जो रियायतें दी थी उन्हें भी इस सरकार ने वापस ले लिया है। इन बढ़ी दरों का असर सीमेन्ट और लोहे पर पड़ेगा और यही असर इस आपदा में अपना घर तक खो चुके लोगों पर पड़ेगा। निश्चित है यह सारे मुद्दे आने वाले सत्र में उठेंगे। सुक्खु सरकार अभी तक अपने वायदों की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठा पायी है। आने वाले लोकसभा चुनावों पर इन मुद्दों का सीधा असर पड़ेगा।